

संक्षिप्त समाचार

पीएम आवास ने दी पक्की छत, महतारी वंदन और पेंशन से मिला आर्थिक सहारा

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत सरकारी योजनाओं से ग्रामीण परिवारों के जीवन में आए बदलाव को तस्वीर सामने आ रही है। बहन्नीडीह विकासखंड के ग्राम पंचायत लखुरी की नर्मदा बाई के परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पक्का घर मिला है। वहीं महतारी वंदन योजना, पेंशन और शौचालय की सुविधा से परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों में भी सहारा मिला है। नर्मदा बाई का परिवार पहले कच्चे मकान में रहता था। बारिश और मौसम की परिस्थितियों के बीच पक्के घर की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पक्का मकान मिलने के बाद परिवार को सुरक्षित छत मिली है। अब परिवार मौसम संबंधी परेशानियों से काफी हद तक राहत महसूस कर रहा है। परिवार को महतारी वंदन योजना और पेंशन का लाभ भी मिल रहा है। नियमित आर्थिक सहायता धरेलू जरूरतों और रोजमर्रा के खर्चों में उपयोगी साबित हो रही है। सीमित आय वाले परिवार के लिए यह सहायता आर्थिक सहारे के रूप में काम कर रही है। इसके साथ ही घर में शौचालय की सुविधा मिलने से परिवार को खुले में शौच की परेशानी से राहत मिली है। इससे स्वच्छता और गरिमा के साथ जीवन जीने की सुविधा भी मिली है। नर्मदा बाई के परिवार को अलग-अलग सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। पीएम आवास योजना ने सुरक्षित छत उपलब्ध कराई, वहीं महतारी वंदन और पेंशन ने आर्थिक जरूरतों में सहयोग दिया। शौचालय की सुविधा से स्वच्छता को बढ़ावा मिला है। पक्के आवास में रहने के बाद परिवार खुद को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा है। सरकारी योजनाओं से मिले इस सहयोग ने परिवार के भविष्य को लेकर उम्मीदें बढ़ाई हैं।

रायपुर में फिर होगा एयरोबेटिक प्रदर्शन

रायपुर। राजधानी रायपुर में राज्योत्सव के दौरान भारतीय वायुसेना का खास एयर शो आयोजित किया जाएगा। 2 नवंबर 2026 को नवा रायपुर के आसमान में वायुसेना की 'सारंग' हेलीकॉप्टर डिस्लेटोम छह हेलीकॉप्टरों के साथ एयरोबेटिक प्रदर्शन करेगी। वहीं 'आकाशगंगा' पैराशूट डिस्लेटोम के प्रशिक्षित पैराडरूपर्स पैराशूट जंप के जरिए अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में वायुसेना के 100 से अधिक अधिकारी और जवान शामिल होंगे। सारंग टीम के छह हेलीकॉप्टर आसमान में अलग-अलग फॉर्मेशन बनाकर एयरोबेटिक करतब दिखाएंगे। इसके अलावा वायुसेना के तीन अन्य हेलीकॉप्टर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना की सारंग टीम स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) 'ध्वज' से प्रदर्शन करती है। टीम का नाम 'सारंग' यानी मोर पर आधारित है और हेलीकॉप्टरों की रंग-संज्ञा भी इसी थीम से प्रेरित है। एयर शो के दौरान आकाशगंगा पैराशूट डिस्लेटोम के प्रशिक्षित पैराडरूपर्स आसमान से छलांग लगाकर पैराशूट के जरिए प्रदर्शन करेंगे। दोनों टीमों का प्रदर्शन राज्योत्सव के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था पर भी फोकस किया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने अधिकारियों को व्यवस्थित पार्किंग, सुगम आवागमन और जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। राज्योत्सव के दौरान होने वाला यह एयर शो प्रदेशवासियों के लिए विशेष आकर्षण रहेगा। आयोजन को लेकर प्रशासन ने भीड़ और यातायात प्रबंधन की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

औषधीय खस की खेती से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ीं परखंडा की महिलाएं

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत कुहूद विकासखंड के ग्राम पंचायत परखंडा की 'धान के कटोरा उत्पादक समिति' खस-सहायता समूह की महिलाओं ने औषधीय एवं सुगंधित फसल खस की खेती से आजीविका का नया रास्ता तैयार किया है। समूह ने 2.50 एकड़ में खस की खेती कर पहली ही फसल में 11.20 क्विंटल उत्पादन किया और इससे 1.12 लाख रुपये की आय अर्जित की। पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए महिलाओं ने सामूहिक श्रम, नियमित देखभाल और नई कृषि पद्धतियों को अपनाकर खस की खेती शुरू की। पहली फसल से मिली आय ने समूह की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है और उन्हें कृषि में फसल विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। परखंडा में योजनांतर्गत 6 एकड़ क्षेत्र में मिश्रित वृक्षारोपण भी किया गया है। इससे आजीविका संवर्धन के साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा दिया जा रहा है। खस की खेती से मिले उत्साहजनक परिणाम के बाद समूह की महिलाएं अब हल्दी की खेती भी कर रही हैं। विभिन्न फसलों को अपनाने से समूह के लिए कृषि आधारित आय के नए विकल्प विकसित हो रहे हैं। परखंडा की महिलाओं की यह पहल सामूहिक प्रयास, फसल विविधीकरण और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के जरिए ग्रामीण महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।

महतारी वंदन की राशि का संदेश आते ही खिल उठता है रेखा का चेहरा

रायपुर। मोबाइल फोन पर महतारी वंदन योजना की राशि खाते में आने का संदेश मिलते ही ग्राम सारवहारा निवासी श्रीमती रेखा कैवर्त के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। परिवार की सीमित आय के बीच हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता ने उन्हें धरेलू जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्चों को संभालने में सहूलियत दी है। अब बच्चों की द्यूशन फीस हो या अपनी सिलाई की दुकान के लिए फल-अस्तर खरीदने का खर्च, इन जरूरतों के लिए उन्हें पहले जैसी चिंता नहीं करनी पड़ती। 42 वर्षीय श्रीमती रेखा कैवर्त गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार से हैं। गौरेला विकासखंड के ग्राम सारवहारा में वे छोटे स्तर पर टेलरिंग का काम करती हैं। इसी आमदनी से वे अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालती हैं। उनके परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है और सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा, घर का खर्च और सिलाई के काम के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना उनके लिए लंबे समय से चुनौती रहा है। रेखा बताती हैं कि पहले महीने उनके के धरेलू खर्च और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों को लेकर उन्हें अक्सर चिंता रहती थी। सिलाई के काम के लिए फल-अस्तर जैसी सामग्री खरीदने के लिए भी पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ऐसे में महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता उनके लिए उपयोगी साबित हो रही है। वह कहती हैं कि हर महीने खाने के धरेलू हजार रुपये आने से भुझे घर के बजटी खर्चों को संभालने में सहूलियत होती है। बच्चों की फीस और सिलाई के सामान के लिए पैसे की व्यवस्था हो जाती है। अब पहले जैसी चिंता नहीं रहती। रेखा के लिए यह सहायता केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने का भरोसा भी है।

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में रोजगार,डिजिटल गवर्नेंस और कौशल विकास की दिशा में तीन महत्वपूर्ण पहल युवाओं को रोजगार और आधुनिक कौशल से जोड़ना हमारी प्राथमिकता

■ नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त उप अभियंताओं को मुख्यमंत्री ने साँपे नियुक्ति पत्र

■ चिप्स और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच हुआ एमओयू, नागरिकों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच होगी और आसान

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में आज मंत्रालय महानदी भवन में रोजगार, डिजिटल गवर्नेंस और कौशल विकास के क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण पहलों को आगे बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में चयनित युवा उप

अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नागरिकों तक शासकीय डिजिटल सेवाओं की पहुंच को अधिक व्यापक और सुविधाजनक बनाने के लिए छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एमओयू किया गया। साथ ही नवा रायपुर में प्रस्तावित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र साँपा गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर, नागरिकों को सरल और पारदर्शी शासकीय सेवाएं तथा नई पीढ़ी को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक कौशल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार रोजगार सृजन, कौशल विकास, डिजिटल गवर्नेंस और आधुनिक अधोसंरचना को एक-दूसरे से जोड़कर विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं और सेवाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी



पूरा होता है, जब उनका लाभ नागरिकों तक आसानी और समयबद्धता के साथ पहुंचे। तकनीक के माध्यम से शासन और नागरिकों के बीच की दूरी कम की जा रही है। वहीं युवाओं को सरकारी सेवाओं के साथ उद्योग, निजी क्षेत्र, उद्यमिता और कौशल आधारित रोजगार के लिए भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने नवा रायपुर अटल नगर विकास

प्राधिकरण में उप अभियंता के पद पर चयनित युवा अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने नवनियुक्त अभियंताओं के अभिभावकों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर भविष्य के छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं का शहर है। यहां आधुनिक अधोसंरचना, गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं और योजनाबद्ध

100 रुपए की बचत से शुरू हुआ सफर,दाल चक्की ने शशिकला को बनाया आत्मनिर्भर.....

रायपुर/ संवाददाता

मॉजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है; पंखों से कुछ नहीं होता, हाँसलों से उड़ान होती है। आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की यह कहावत छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमेशा किसी बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दृढ़ संकल्प, अनवरत मेहनत और सही मार्गदर्शन से छोटी-सी शुरुआत भी सफलता की एक नई इबारत लिख सकती है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला विकासखंड अंतर्गत ग्राम बिलाईगढ़ की निवासी श्रीमती शशिकला साहू की कहानी आज प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा की एक नई किरण बनकर उभरी है। कभी साधारण आर्थिक परिस्थितियों के बीच परिवार की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित रहने वाली शशिकला, आज स्वयं की आटा और दाल चक्की को एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। 'सेवा संकल्प अभियान' के दौरान सामने आई उनकी यह प्रेरक यात्रा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और महिला श्रमशक्ति के अनूठे मेल की सुंदर मिसाल पेश करती है। पति श्री



रूपनारायण साहू के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए शशिकला के मन में लंबे समय से स्वयं की आय का एक स्थायी साधन खड़ा करने की तीव्र इच्छा थी। उनकी इस सोच को धरातल पर उतारने का अवसर तब मिला, जब उन्होंने 11 सितंबर 2018 को गांव के 'दुर्गा' स्वयं सहायता समूह' से जुड़कर स्वावलंबन की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया। इस सफर की शुरुआत बेहद सामान्य थी, जहाँ उन्होंने समूह में हर महीने महज 100 रुपये की छोटी बचत से शुरुआत की। अनुशासन और नियमितता के बल पर जमा की गई यही छोटी-सी राशि आगे चलकर उनके स्वरोजगार की मजबूत बुनियाद बनी।

मोदी की योजना से मिला सहारा दिलीप और सावित्री की जोड़ी ने कोरिया में जगाई गुड मॉर्निंग...

रायपुर/ संवाददाता

कोरिया में अब कई परिवारों की सुबह सिर्फ 'गुड मॉर्निंग' संदेश से नहीं, बल्कि 'गुड मॉर्निंग बेकरी' के ताजा ब्रेड, टोस्ट, बिरिकट और केक से भी होती है। ग्राम ओड़ुंगी के दिलीप और सावित्री गुप्ता की जोड़ी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का लाभ उठाकर अपने सपने को कारोबार में बदला है।कभी आर्थिक कठिनाइयों से जूझने वाला यह परिवार आज आत्मनिर्भर है और अपने साथ करीब 10 लोगों को रोजगार दे रहा है। स्नातक तक पढ़ी सावित्री गुप्ता



और दसवीं तक पढ़े उनके पति दिलीप के लिए अपना व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले दिलीप करीब पाँच वर्षों तक दूसरी बेकरी में काम करते रहे। इस दौरान उन्होंने बेकरी उत्पादन, गुणवत्ता, बाजार और ग्राहकों की जरूरतों को करीब से

समझा। यही अनुभव आगे चलकर उनके अपने कारोबार की ताकत बना। वर्ष 2023-24 में बैकुंठपुर विधायक श्री भैयालाल राजवाड़े के माध्यम से दिलीप को पीएमईजीपी योजना की जानकारी मिली। योजना को समझने के बाद दिलीप और सावित्री ने तय किया कि अब दूसरों के लिए काम करने के बजाय अपना रोजगार खड़ा किया जाए। सावित्री ने पीएमईजीपी के माध्यम से करीब 10 लाख रुपये का ऋण लेकर अपनी जमीन पर बेकरी उद्योग स्थापित किया। परिवार ने भी करीब 2 से 3 लाख रुपये की राशि लगाई। करीब 10 से 12 हजार वर्गफीट क्षेत्र में 'गुड मॉर्निंग बेकरी' की शुरुआत हुई।

सीएम हेल्पलाइन 1076 : आमजन की समस्याओं के समाधान का भरोसेमंद सेतु शिकायत से समाधान तक नागरिकों को मिल रहा मार्गदर्शन और सहायता

■ सरगुजा की आराधना के आधार कार्ड में जन्मतिथि की त्रुटि हुई दूर, उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की राह हुई आसान

रायपुर/ संवाददाता

आम नागरिक को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उसकी बात सहजता से शासन-प्रशासन तक पहुंचे, इस दिशा में सीएम हेल्पलाइन 1076 महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। नागरिक अपनी समस्याएं और शिकायतें हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाता है। इससे शिकायत के समाधान के साथ नागरिकों को उचित प्रक्रिया और आवश्यक

दस्तावेजों के संबंध में मार्गदर्शन भी मिल रहा है। सीएम हेल्पलाइन की उपयोगिता केवल शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं है। कई बार नागरिक को यह जानकारी नहीं होती कि उसकी समस्या का समाधान किस विभाग से होगा, कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे और किस प्रक्रिया का पालन करना होगा। ऐसी परिस्थितियों में हेल्पलाइन नागरिक और संबंधित विभाग के बीच सेतु का काम करते हुए समाधान की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर रही है। सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित विषय को उचित स्तर पर भेजा जाता है। आवश्यकता के अनुसार संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ता से संपर्क कर समस्या की जानकारी लेते हैं और आगे की प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन देते हैं। इससे नागरिक को अपनी समस्या से दर्ज करा सकते हैं, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाता है। इससे शिकायत के समाधान के साथ नागरिकों को उचित प्रक्रिया और आवश्यक



साबित हो रही है। जानकारी के अभाव में कई बार नागरिक गलत कार्यालय या प्रक्रिया में समय और संसाधन खर्च करते हैं। सही विभाग, आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी मिलने से समस्या के निराकरण की राह आसान होती है। सरगुजा जिले के ग्राम करिया की छात्रा आराधना सिंह का मामला सीएम हेल्पलाइन से मिली सहायता का उदाहरण है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कॉलेज में प्रवेश की तैयारी के दौरान उन्हें

पता चला कि उनके आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत दर्ज है और वास्तविक जन्मतिथि से लगभग तीन वर्ष का अंतर है। आराधना ने आधार केंद्र और डाकघर के माध्यम से जन्मतिथि में सुधार कराने का प्रयास किया, लेकिन अधिक अंतर होने के कारण सामान्य प्रक्रिया से संशोधन नहीं हो सका। समस्या का समाधान नहीं मिलने पर उनके चाचा ने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद संबंधित अधिकारियों ने परिवार से संपर्क किया और जन्म प्रमाण पत्र, शपथ पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज तैयार कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने का मार्गदर्शन दिया। आराधना ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रक्रिया पूरी की और लगभग एक सप्ताह में उनके आधार कार्ड में जन्मतिथि का सुधार हो गया। दस्तावेज में सुधार होने से आराधना के लिए कॉलेज में प्रवेश और भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में आने वाली संभावित परेशानी दूर हुई। उन्होंने इस सहायता के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और शासन-

विकास को निरंतर विस्तार दिया जा रहा है। नवनियुक्त अभियंताओं को इस आधुनिक शहर के निर्माण और विकास में योगदान देने का महत्वपूर्ण अवसर मिला है। उन्होंने युवा अभियंताओं से कहा कि वे अपने ज्ञान और तकनीकी दक्षता का उपयोग जनहित में करते हुए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। विभिन्न विभागों में नियमित भर्तियां की जा रही हैं और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाया गया है। सभी युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं हो सकती, इसलिए राज्य सरकार उद्योग, निजी क्षेत्र, उद्यमिता, स्टार्टअप और कौशल विकास के माध्यम से भी व्यापक अवसर तैयार कर रही है।

नस्ल सुधार से बढ़ा दूध उत्पादन,नेहर साय के परिवार की आजीविका को मिला नया संबल..

■ पशुधन विकास विभाग की सलाह पर देशी गाय में कराया कृत्रिम गर्भाधान, साहीवाल बछिया और क्रॉसिंग से मिली गिर नस्ल की गाय

रायपुर/ संवाददाता

परंपरागत पशुपालन में वैज्ञानिक तरीके और नस्ल सुधार को अपनाकर ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका को मजबूत कर सकते हैं। सरगुजा जिले की ग्राम पंचायत देवरी निवासी श्री नेहर साय कुजूर ने पशुधन विकास विभाग के मार्गदर्शन से इसी दिशा में कदम बढ़ाया है। देशी गाय में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार और पशुओं



की बेहतर देखभाल से दूध उत्पादन बढ़ा है। अब पशुपालन से होने वाली दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक बन रही है। नेहर साय बताते हैं कि पहले उनके पास सामान्य देशी गाय थीं। पशुधन विकास विभाग के पशु चिकित्सकों से सलाह मिलने के बाद उन्होंने गाय में कृत्रिम गर्भाधान कराया। इससे उन्हें साहीवाल नस्ल की बछिया प्राप्त हुई। इसके बाद नस्ल सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए क्रॉसिंग के माध्यम से गिर

नस्ल की गाय भी प्राप्त हुई। बेहतर नस्ल और उचित पशुपालन प्रबंधन का असर दूध उत्पादन में दिखाई दे रहा है। वर्तमान में उनकी दोनों गायों से प्रतिदिन लगभग 8 से 10 लीटर दूध प्राप्त हो रहा है। दोनों गायों के बच्चे भी हैं। दूध उत्पादन से होने वाली आय ने पशुपालन को नेहर साय के परिवार के लिए आजीविका के उपयोगी साधन के रूप में मजबूत किया है। नस्ल सुधार से मिले परिणामों ने उन्हें पशुपालन को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। अब वे अपने पशुधन की संख्या बढ़ाकर इस गतिविधि को और बेहतर तरीके से विकसित करना चाहते हैं। नेहर साय बताते हैं कि पशुधन विकास विभाग के चिकित्सक समय-समय पर पशुओं के स्वास्थ्य, आहार, नस्ल सुधार और उचित देखभाल के संबंध में आवश्यक सलाह देते हैं।

कृषि विकास के लिए मिले 181.99 करोड़ रुपए-नेताम

रायपुर। संवाददाता

राष्ट्रीय कृषि मंत्रियों के सम्मेलन 'रबी अभियान 2026' के अवसर पर 28-29 सितंबर को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सीजन्य मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र और किसानों के हित में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत कुल 181.99 करोड़ रुपये की द्वितीय मद की राशि जारी किए जाने की जानकारी देते हुए मंत्री रामविचार नेताम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। गौरतलब है कि कृषि मंत्री राम विचार नेताम के निरंतर प्रयासों से प्रदेश के किसानों को समृद्धि मिल

रही है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को जारी 181.99 करोड़ रुपये में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 91.20 करोड़ रुपये तथा कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 90.79 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस राशि से राज्य में कृषि से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों को गति मिलेगी तथा किसानों को इसका लाभ प्राप्त होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने तथा राज्य के साथ मित्रकर कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ सरकार इस राशि का समयबद्ध एवं प्रभावी उपयोग करते हुए राज्य के किसानों तक इसका अधिकतम लाभ पहुंचाएगी।

प्रशासन के प्रति आधार व्यक्त किया। नागरिकों के सामने आने वाली समस्याएं अलग-अलग हो सकती हैं। किसी विद्यार्थी के दस्तावेज में त्रुटि हो सकती है, किसी किसान को शासकीय सेवा या योजना से संबंधित कठिनाई हो सकती है, किसी व्यक्ति का आवेदन लंबित हो सकता है तो किसी नागरिक को विभागीय प्रक्रिया की सही जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। सीएम हेल्पलाइन 1076 ऐसे मामलों में नागरिकों को अपनी समस्या शासन के समक्ष रखने का माध्यम उपलब्ध कराती है। विद्यार्थी शिक्षा और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं, किसान शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं से संबंधित कठिनाइयों और महिलाएं विभिन्न शासकीय सेवाओं से जुड़े विषयों को हेल्पलाइन के माध्यम से सामने रख सकती हैं। बुजुर्ग और अन्य नागरिक भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी समस्याओं के संबंध में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकों की समस्याओं को सुनना, उन्हें सही प्रक्रिया तक पहुंचाना और संबंधित विभाग के माध्यम से निराकरण की दिशा में कार्रवाई करना सुशासन का महत्वपूर्ण आधार है।



संपादकीय

अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने व्यावसायिक चालकों के खिलाफ विज्ञापन में ‘मिस्टर सिंह’ का नाम देकर नस्ली पूर्वाग्रह दर्शाया। सिख समुदाय के कड़े विरोध के बाद विवादित पोस्टर वापस लेना पड़ा। इस दौर में ‘एक विश्व, एक परिवार’ या ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ जैसे नारों के साथ दुनिया के आगे का रास्ता तय करने की बातें की जा रही हैं, उसमें अगर

किसी खास समूह या वर्ग को लक्षित करके उसे हाशिये से बाहर करने का संदेश प्रचारित किया जाए, तो इससे ज्यादा अफसोसनाक और बुरा हो सकता है।अमेरिका में गृह सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस वाले व्यावसायिक चालकों के खिलाफ अपने अभियान को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार की गई छवियों का इस्तेमाल किया, जिसमें

अमेरिका में ‘दफा हो जाओ मिस्टर सिंह’, विवादित पोस्टर, सिख समुदाय में भारी आक्रोश

यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदारों पर सौ प्रतिशत तक शुल्क लगाने का अधिकार देता है। भारत और चीन इसके निशाने पर हैं। इसके पीछे अमेरिकी रणनीति रूस की ऊर्जा आय को चोट पहुंचाने की है, ताकि यूक्रेन युद्ध के लिए मास्को को मिलने वाले आर्थिक संसाधनों पर दबाव बनाया जा सके। विधेयक में रूस के ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों के साथ-साथ प्रतिबंधों से बचने वाले उसके जख्मी बड़े पर भी शिकंजा कसने का प्रावधान है।

मोदी को ‘धमकाना’ ट्रंप को पड़ा भारी! रूसी तेल पर अमेरिका के नए दांव का भारत ने दिया करारा जवाब

(नीरज कुमार दुबे)

हम आपको बता दें कि जिस विधेयक को अमेरिकी कांग्रेस में पहली बार अप्रैल 2025 में पेश किया गया था, वह करीब डेढ़ साल तक अमेरिकी राजनीति और ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं के बीच अटका रहा। लेकिन इस महीने यानि सितंबर 2026 में तस्वीर अचानक बदल गई। कहने को तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शायद वह मोदी को अब तक अच्छे से जान ही नहीं पाए हैं। देखा जाये तो जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते नहीं, वह अक्सर धमकियों, प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के सहारे उन्हें झुकाने का सपना देखते हैं। लेकिन मोदी का संकल्प साफ है कि भारत के हितों से समझौता नहीं होगा और देश को किसी विदेशी दबाव के आगे झुकने नहीं देना है। उनके हर फैसले में यही दृढ़ता दिखाई देती है। दूसरी ओर, ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही भारत पर दबाव बनाने के लिए शुल्क, व्यापारिक दबाव और रूस से तेल खरीद बंद कराने जैसी तमाम कोशिशें कीं, लेकिन नई दिल्ली ने हर बार अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च रखा। अब अमेरिका एक बार फिर टैरिफ रूपी आर्थिक हथियार लेकर मैदान में उतरा है, लेकिन मोदी सरकार ने भी बिना देर किए वाशिंगटन को साफ संदेश दे दिया है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हित किसी विदेशी दबाव की कीमत पर तय नहीं होंगे। हम आपको बता दें कि जिस विधेयक को अमेरिकी कांग्रेस में पहली बार अप्रैल 2025 में पेश किया गया था, वह करीब डेढ़ साल तक अमेरिकी राजनीति और ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं के बीच अटका रहा। लेकिन इस महीने यानि सितंबर 2026 में तस्वीर अचानक बदल गई। भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सक्रिय कूटनीतिक भागीदारी के कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रूस और ईरान पर नए प्रतिबंधों वाला विधेयक पारित कर दिया। घटनाक्रम का समय भले ही संयोग हो, लेकिन संदेश बेहद स्पष्ट है कि वाशिंगटन रूस से जुड़े देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अब शुल्क को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने को तैयार है। लेकिन भारत ने भी अमेरिका को उसी क्षण जवाब दे दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टुक कहा कि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत बदलती बाजार परिस्थितियों के अनुसार अलग-



अलग क़ोतों से ऊर्जा खरीदता रहेगा। इतना ही नहीं, नई दिल्ली ने अमेरिका को याद दिलाया कि इस कदम के भारत-अमेरिका संबंधों के साथ-साथ पूरे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में अमेरिकी पक्ष को पहले ही उच्च स्तर पर स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि भारत अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। यानी अमेरिका शुल्क की धमकी दे सकता है, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा की कीमत पर किसी विदेशी दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल, जिस विधेयक को अब ‘लिटंडे ओ. ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम 2026’ कहा जा रहा है, उसकी कहानी डेढ़ साल पुरानी है। अप्रैल 2025 में लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमैथल ने रूस के खिलाफ कड़े प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिबंधों की पहल की थी। इसके बाद लंबे समय तक इसे कांग्रेस और प्रशासन के बीच समर्थन जुटाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। जुलाई 2026 में व्हाइट हाउस से सहमति बनने के बाद इसकी राह खुली। अगस्त में सीनेट ने इसे 86 के मुकाबले 11 मतों से पारित किया और 16 सितंबर को प्रतिनिधि सभा ने 262 के मुकाबले 159 मतों से इसे मंजूरी दे दी। यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदारों पर सौ प्रतिशत तक शुल्क लगाने का अधिकार देता है। भारत और चीन इसके निशाने पर हैं। इसके पीछे अमेरिकी रणनीति रूस की ऊर्जा आय को चोट पहुंचाने की है, ताकि यूक्रेन युद्ध के लिए मास्को को मिलने वाले आर्थिक संसाधनों पर दबाव बनाया जा सके। विधेयक में रूस के ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों के साथ-साथ प्रतिबंधों से बचने वाले उसके जख्मी बड़े पर भी शिकंजा कसने का प्रावधान है। लेकिन अमेरिका शायद यह भूल रहा है कि भारत रूस से तेल किसी राजनीतिक



एहसान के लिए नहीं खरीद रहा। भारत की जरूरत है सस्ती, विश्वसनीय और लगातार उपलब्ध ऊर्जा। 2022 में रूस भारत के लिए कोई बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता नहीं था। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप द्वारा रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए जाने से रूस का कच्चा तेल भारी छूट पर उपलब्ध हुआ और भारत ने अपने आर्थिक हित में इसे खरीदना शुरू किया। इसके बाद रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। वित्त वर्ष 2026 में भारत रूसी तेल बंद करना केवल रूस के खिलाफ हिस्सेदारी आधे से भी ज्यादा पहुंच गई। इसके अलावा, आज वैश्विक परिस्थितियों को देखें तो वह भी सामान्य नहीं हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध और आपूर्ति संकट ने तेल बाजार को बुरी तरह प्रभावित किया है। होमूज जलडमरूमध्य में बाधाएं हैं और वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत भी दबाव में हैं। भारत 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन रूस और पश्चिम एशिया उसकी ऊर्जा सुरक्षा के मुख्य आधार बने हुए हैं। ऐसे समय में अचानक रूसी तेल बंद करना केवल रूस के खिलाफ फैसला नहीं होगा, बल्कि भारत की अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकता है। यही कारण है कि पिछले साल अमेरिकी दंडात्मक शुल्क भी भारत को रूसी तेल से पूरी तरह दूर नहीं कर सके। भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल की खरीद में बड़ी कटौती तब की जब रूस की प्रमुख तेल कंपनियों पर सीधे प्रतिबंध लगाए गए और व्यापार करना कठिन हो गया। लेकिन जैसे ही पश्चिम एशिया में आपूर्ति संकट गहराया, भारत ने फिर रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी। जुलाई में रूसी तेल की खरीद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इससे एक बात साफ होती है कि भारत के लिए ऊर्जा

सुरक्षा कोई सौदेबाजी का विषय नहीं है।

यहां इस पूरे घटनाक्रम का सामरिक महत्व सामने आता है। अमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहता है। जबकि रूस भारत की ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। चीन भी रूसी ऊर्जा का बड़ा खरीदार है। साथ ही भारत एक साथ अमेरिका, रूस, चीन, ईरान तथा पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपने हितों का संतुलन साध रहा है। ऐसे में नई दिल्ली के सामने चुनौती किसी एक खेमे में जाने की नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बचाए रखने की है। इसके अलावा, ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी की पुतिन और जिनपिंग के साथ बढ़ती कूटनीतिक निकटता ने जिस बदलती विश्व व्यवस्था की तस्वीर अमेरिका के सामने रखी, उसके कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी कांग्रेस का रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने वाला कदम कई सवाल खड़े करता है। सवाल उठता है कि क्या वाशिंगटन को यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि दुनिया अब उसकी शलों पर नहीं चलती? देखा जाये तो भारत, रूस और चीन का एक मंच पर आना और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था तथा संप्रभु समानता की क्वालत कराना उस अमेरिकी वर्चस्ववादी सोच के लिए सीधी चुनौती है, जिसमें लंबे समय से आर्थिक ताकत को कूटनीतिक दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन बदलती दुनिया का संदेश साफ है। भारत सहित उभरती शक्तियां अब अपने राष्ट्रीय हितों का फैसला किसी बाहरी राजधानी के इशारे पर नहीं करेंगी।

खैर...अब गेंद ट्रंप के पाले में है। अमेरिकी कांग्रेस ने उन्हें सौ प्रतिशत तक शुल्क लगाने की शक्ति दे दी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सौ प्रतिशत शुल्क स्वतः लागू हो गया। अंतिम निर्णय ट्रंप को करना है। शुल्क कितना होगा, किन वस्तुओं पर लागू होगा और कब लागू होगा, इन सबका असर भारत-अमेरिका व्यापार पर पड़ेगा। भारत का रुख स्पष्ट है कि ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं होगा, विकल्पों का विस्तार जारी रहेगा, अमेरिका से बातचीत जारी रहेगी और राष्ट्रीय हितों पर कोई एकरतफ समझौता नहीं होगा। अमेरिकी शुल्क चाहे जितना बढ़ा हो, भारत के लिए असली सवाल किसी एक देश को खुश करना नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्वायत्तता सुरक्षित रखना है। विदेश मंत्रालय पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। भारत अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

मातहत एक विभाग के जरिए हो। स्वाभाविक ही अमेरिका में रहने वाले सिख समुदाय सहित अन्य लोगों ने भी इस पर तीखी आपत्ति जाहिर की और पोस्टर को ‘नस्लवादी’ और ‘भारत विरोधी’ बताया।हो सकता है कि अमेरिका में कुछ ऐसे सड़क हादसे हुए हों, जिनमें चालक की पहचान वहां अवैध रूप से रहने वाले भारतीय के रूप में पाई गई हो, लेकिन इसका

मतलब यह नहीं हो जाता कि इस बहाने ‘सिंह’ उपनाम से पहचाने जाने वाले समूचे समुदाय को निशाना बनाया जाए। लेकिन सवाल है कि आधुनिक मूल्यों का वाहक होने का दावा करने वाले अमेरिका में आज भी इस तरह की संकीर्ण नस्ली दृष्टि कैसे फल-फूल रही है कि वह किसी सरकारी मकदमे के विज्ञापन में भी अभिव्यक्त हो जाती है!

चीन के साथ मिलकर गुस्ताखी कर रहा था पाकिस्तान,तभी भारत ने सीमा आयुक्त आयोग को ही खारिज कर दिया

(नीरज कुमार दुबे)

हम आपको बता दें कि इस आयोग की पहली बैठक इस्लामाबाद में हुई। पाकिस्तान ने इसे द्विपक्षीय संबंधों की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए सीमा प्रबंधन, संयुक्त सीमा सर्वेक्षण, व्यापारिक प्रवाह और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की बात कही। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संवेदनशील भूभाग को लेकर चीन और पाकिस्तान ने एक बार फिर ऐसी कवायद शुरू की है, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। पाकिस्तान और चीन द्वारा बनाए गए तथाकथित सीमा संयुक्त आयोग की पहली बैठक के बाद भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि इस आयोग का कोई कानूनी आधार नहीं है और भारतीय भूभाग को लेकर पाकिस्तान को चीन के साथ किसी भी तरह की व्यवस्था करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने दो टुक कहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं तथा कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को लेकर भारत-पाकिस्तान की कोई भी गतिविधि चीन की संप्रभुता को प्रभावित नहीं कर सकती।

हम आपको बता दें कि इस आयोग की पहली बैठक इस्लामाबाद में हुई। पाकिस्तान ने इसे द्विपक्षीय संबंधों की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए सीमा प्रबंधन, संयुक्त सीमा सर्वेक्षण, व्यापारिक प्रवाह और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की बात कही। बैठक की सह-अध्यक्षता चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा एवं महासागरीय मामलों से जुड़े अधिकारी ली या और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में चीन मामलों के महानिदेशक बिलाल महमूद चौधरी ने की।

उधर, भारत ने इस पहल को महज दो देशों के बीच सामान्य सीमा सहयोग मानने से साफ इंकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के बीच ऐसी कोई सीमा नहीं है, जिसे भारतीय भूभाग के संदर्भ में दोनों देश मिलकर वैध रूप दे सकें। भारत ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्रशासित क्षेत्रों को अपना अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा बताते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपने अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों के बारे में किसी व्यवस्था में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है।

देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम की जड़ 1963 में हुए चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते तक जाती है। उस समझौते के तहत पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी के लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को चीन के साथ सीमा

निर्धारण की व्यवस्था में शामिल किया था। हालांकि भारत ने इसे कभी मान्यता नहीं दी। भारत सरकार ने संसद में भी स्पष्ट किया है कि वह इस तथाकथित समझौते को अवैध और अमान्य मानती है तथा शक्सगाम घाटी को भारतीय क्षेत्र मानती है।

इसका इतिहास 1947-48 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर रियासत की स्थिति से जुड़ता है। भारत का आधिकारिक रुख है कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया और बाद में उसी क्षेत्र से चीन के साथ समझौता किया। इसलिए पाकिस्तान द्वारा उस भूभाग के संबंध में चीन के साथ कोई भी समझौता अपने आप में अधिकांहीन है।

हम आपको बता दें कि शक्सगाम घाटी और कराकोरम केवल मानचित्र पर दिखाई देने वाली दृश्य पहाड़ी जमीन नहीं है। यह इलाका चीन के शिनचांग क्षेत्र, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और लद्दाख के बीच स्थित अत्यंत संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र है। इसी व्यापक भूभाग में चीन-पाकिस्तान संपर्क की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाएं विकसित हुई हैं। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारों का एक हिस्सा भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिस पर भारत लगातार आपत्ति जताता रहा है।

रणनीतिक दृष्टि से इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि भारत एक साथ पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर क्षेत्रीय दबाव का सामना करता है। भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले वर्षों में सैन्य तनाव और तैनाती ने इस चुनौती को और गंभीर बनाया है। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों ने तनाव कम करने की दिशा में कुछ कदम उठाए, लेकिन सीमा विवाद का मूल प्रश्न अभी भी अनुसुलझा है। ऐसे समय में कराकोरम क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त सीमा तंत्र को सक्रिय करना केवल प्रशासनिक सहयोग के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसका संभावित रणनीतिक अर्थ यह है कि दोनों देश उस भूभाग में अपने पारस्परिक समन्वय को संस्थागत रूप देना चाहते हैं, जोकि भारत का है। इससे भविष्य में सड़क, व्यापार, आवागमन, सर्वेक्षण और सीमा प्रबंधन जैसी गतिविधियों को अधिक संगठित आधार मिल सकता है।

उधर, भारत का जवाब संप्रभुता की स्पष्ट रेखा खींचने वाला संदेश है। नई दिल्ली ने साफ कहा है कि चीन-पाकिस्तान की ऐसी कोई भी सीमा-संबंधी कवायद भारतीय संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती।

नाराज फूपाओं के अलावा बेफिक्र मामाओं से भी सावधान

(डा. रवीन्द्र अरजरिया)

जल प्रलय के स्थितियों के बाद अब देश में सांकेतिक प्रहारों की बाढ़ आ गई है। भारतीय राजनीति में रिश्तों के प्रतीकों का प्रयोग नया नहीं है। कभी कोई नेता स्वयं को जनता का सेवक बताता है, तो कोई परिवार के सदस्य की तरह जनता के सुख-दुख में साथ होने का दावा करता है। इसी श्रंखला में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के लिए ‘नाराज फूफा’ शब्द का व्यंग्यात्मक प्रयोग किया। प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद सत्ताधारी भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी विपक्ष की भूमिका को ‘नाराज फूफा’ से जोड़ते हुए कहा कि देश की प्रगति के बावजूद विपक्ष हर उपलब्धि में आपत्ति तलाशता है। यह व्यंग्य केवल शब्दों का खेल नहीं है। इसके पीछे भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को लेकर एक गंभीर बहस छिपी है। लोकतंत्र में सरकार के हर निर्णय पर प्रश्न उठाना विपक्ष का अधिकार तो है लेकिन प्रश्न और पूर्वाग्रह, समीक्षा और विरोध, तथ्य और राजनीतिक व्याख्या के बीच अंतर बनाए रखना भी उसका कर्तव्य है। जब हर सरकारी निर्णय को संदेह की दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तब स्वस्थ लोकतांत्रिक निगरानी और राजनीतिक नकारात्मकता के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर यह अंतर और महत्वपूर्ण हो जाता है। इतिहास गवाह है कि सन् 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्षी दलों ने विशेष संसद सत्र और सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए लगभग 12 विपक्षी दलों ने परलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, संघर्षकाम और नियंत्रण रेखा की स्थिति पर संसद में चर्चा का नारा बुलंद किया था। यह मांग लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा तो बन सकती थी किन्तु सैन्य अभियानों की वास्तविक समय की जानकारी, सैनिकों की तैनाती तथा संवेदनशील रणनीतिक विवरण सार्वजनिक करना राष्ट्रीय सुरक्षा के

लिए एक बड़ा जोखिम भी पैदा कर सकता था। ऐसे में ‘गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करो’ और ‘सरकार से जवाब मांगो’ के बीच का अन्तर समझना भी बेहद जरूरी है। संसद में जवाबदेही मांगना लोकतंत्र अधिकार हो सकता है किन्तु सैनिकों की सुरक्षा अथवा भविष्य की कार्रवाई प्रभावित करने वाली जानकारी का सार्वजनिक करना सुरक्षाबलों को अपेक्षित कुर्ये में धकेलने जैसा ही



होता। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं लोकसभा में कहा था कि सैन्य नेतृत्व को कार्रवाई के समय, स्थान और तरीके के संबंध में स्वतंत्रता दी गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीतिक विमर्श में पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन की कसौटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। विपक्षी दलों पर सरकार के प्रत्येक निर्णय की आलोचना करने, नीतियों की नकारात्मक व्याख्या करने अथवा संदेह पैदा करने के आरोप समय-समय पर सत्ता पक्ष द्वारा लगाये जाते रहे हैं जिस पर विपक्ष सरकार से सबल कराना लोकतंत्र की अनिवार्य प्रक्रिया का अंग मानकर आरोपों का खण्डन करता रहा है। समस्या विरोध में नहीं बल्कि विरोध के तरीके में खोजी जानी चाहिए। यदि तथ्य सामने रखकर नीति की कमियां बताई जाएं तो वह लोकतांत्रिक विमर्श को मजबूत करता है लेकिन यदि अभूरी जानकारी, अनुमान अथवा मनगढ़ंत व्याख्याओं

से जनमानस में भ्रम पैदा किया जाए, तो उसका नुकसान सरकार से कहीं आगे समाज और संस्थाओं तक पहुंच सकता है।

ऐसे में ‘नाराज फूफा’ की राजनीति का दूसरा छोर ‘बेफिक्र मामा’ तक भी पहुंचता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ‘मामा’ संबोधन भी इसी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा रहा है। चुनावी राजनीति में जनता को तत्काल राहत देने वाली महिलाओं को प्रत्यक्ष नकद सहायता, मुफ्त वाहन, बिजली, कृषि सहायता अथवा अन्य सुविधाएं देना सामाजिक सुरक्षा का माध्यम हो सकता है, परंतु हर ऐसी योजना का मूल्यांकन उसके दीर्घकालीन वित्तीय प्रभाव के आधार पर भी होना चाहिए। मध्य प्रदेश इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है जहां ‘लाइली लक्ष्मी’ और ‘लाइली बहना’ योजनायें लागू हैं। लाइली लक्ष्मी योजना बालिकाओं से संबंधित पुरानी योजना है जबकि महिलाओं को प्रत्यक्ष मासिक सहायता देने वाली मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना बाद में लागू की गई। सन् 2026-27 के बजट में लाइली बहना योजना के लिए 23,883 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और पंजीकृत महिलाओं की संख्या लगभग 1.25 करोड़ बताई गई है। इसी बजट विवरणों के अनुसार राज्य का सन् 2026-27 का राजकोषीय घाटा 71,458 करोड़ रुपये अर्थात जीएसडीपी का 3.9 प्रतिशत अनुमानित है तथा वर्ष के अंत तक बकाया देनदारियां जीएसडीपी के 32.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। यहां प्रश्न महिलाओं को सहायता देने का विरोध करना नहीं है

बल्कि उसकी स्थिरता का है। पीआरएस के राज्य वित्त संबंधी अध्ययन के अनुसार सन् 2025-26 में 12 राज्यों ने महिलाओं को बड़े पैमाने पर बिना शर्त नकद हस्तांतरण वाली योजनाएं लागू कीं। इन पर राज्यों का संयुक्त अनुमानित खर्च 1.68 लाख करोड़ रुपये था जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.5 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में भी सन् 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्राओं के लिए लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत शीघ्र ही मुफ्त स्कूटी वितरण की घोषणा की जो सन् 2022 के विधानसभा चुनाव के वादों में शामिल था। सरकारों को किसी भी मुफ्त सुविधा के साथ खरीद, वितरण, रखरखाव और भविष्य के वित्तीय भार का आकलन भी करना चाहिये। गरीब परिवार की छात्रा की स्कूटी के रखरखाव, परिचालन का भार उसके तंगहाल परिवार के वित्तीय प्रबंधन पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का सन् 2026-27 बजट लगभग 8.51 लाख करोड़ रुपये के व्यय और 1.18 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का अनुमान रखता है। राज्य की बकाया देनदारियां जीएसडीपी के 23.1 प्रतिशत अनुमानित हैं। इन कल्याणकारी योजनाओं का खर्च उत्पादक निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन की क्षमता को पूरी तरह प्रभावित करता है। देश के लोकतंत्र को न ‘नाराज फूफाओं’ की जरूरत है और न ऐसे ‘बेफिक्र मामाओं’ की जो आज की लोकप्रियता के लिए कल के वित्तीय बोझ की चिंता छोड़ दें। विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार से सवाल करे, लेकिन प्रमाण और वैकल्पिक नीति के साथ। सरकार का दायित्व है कि वह जनकल्याण करे लेकिन घोषणाओं के साथ वित्तीय अनुशासन और परिणामों का हिसाब भी दे। राजनीति में विरोध जरूरी है, कल्याण भी जरूरी है मगर उससे भी कहीं अधिक जरूरी है दोनों की मर्यादायें और विवेक।

सेवा संकल्प अभियान 2026 : वृद्धजन समाज की अमूल्य धरोहर, उनके अनुभव और आशीर्वाद से मिलती है नई पीढ़ी को दिशा- विधायक अटामी

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिला ग्रंथालय में आयोजित हुआ जिला स्तरीय वृद्धजन सम्मान समारोह

दत्तेवाड़ा। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला ग्रंथालय में जिला स्तरीय वृद्धजन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों का जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा श्रीफल, शाल एवं फूलमाला भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच के साथ जरूरतमंद बुजुर्गों को सहायक उपकरण भी प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री चैतराम अटामी ने सभी वरिष्ठजनों को नमन करते हुए कहा कि इतने बुजुर्गों के एक साथ दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त होना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने मां दत्तेश्वरी से प्रार्थना करते हुए कहा कि सभी पर बुजुर्गों की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे। उन्होंने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों के जन्म से लेकर उनके पालन-पोषण और संस्कार देने तक अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। परिवार में बच्चों को जीवन की पहली सीख और संस्कार माता-पिता एवं बुजुर्गों से ही प्राप्त



होते हैं, जो आगे चलकर उनके व्यक्तित्व और समाज की नींव बनते हैं। विधायक अटामी ने कहा कि भारतीय समाज में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर करने की परंपरा रही है। आज भी ग्रामों में आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रमों, ग्राम सभाओं पंचायतों में वरिष्ठजनों को ही अध्यक्षता हेतु आमंत्रित किया जाता है, प्रमुखता भी दी जाती है। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से परिवार, समाज और गांव को सही दिशा मिलती है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हमारे लिए ईश्वर के समान हैं और उनका सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है।

उन्होंने समाज कल्याण विभाग को सम्मान समारोह के आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि जो वरिष्ठजन कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, उनके घर जाकर भी उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में विधायक श्री अटामी ने वरिष्ठ नागरिकों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नंदलाल मुड़ामी ने कहा कि वृद्धजन हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। दत्तेवाड़ा के विकास और निर्माण में वरिष्ठ नागरिकों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। विभिन्न विभागों में सेवाएं देने वाले

सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों तथा माताओं-बहनों ने अपनी मेहनत, अनुभव और योगदान से जिले को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जिन बुजुर्गों ने अपने बच्चों और समाज के भविष्य के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, उनके जीवन में वृद्धाश्रम जैसे आश्रय स्थलों की आवश्यकता होना समाज के लिए एक चिंतनीय विषय है। प्रत्येक बुजुर्ग को अपने परिवार में सम्मान, स्नेह और अपनाना मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हम युवा हैं, लेकिन समय के साथ हम भी इसी अवस्था में पहुंचेंगे। जनप्रतिनिधियों के रूप में क्षेत्र की सेवा करते समय बुजुर्गों का अनुभव और मार्गदर्शन हमें सही दिशा प्रदान करता है।

स्वास्थ्य परीक्षण के साथ वरिष्ठ नागरिकों को दिए गए सहायक उपकरण- कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यकतानुसार दवाइयां प्रदान की गईं।

घायल मरीज को अपनी ही स्कूटी के लिए भटकना पड़ा, जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था कठघरे में



तीन टांके लगे पैर के साथ परिसर में तलाशता रहा मीडिया कर्मी; सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार को लेकर भी शिकायतें, अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

दत्तेवाड़ा :- जिला अस्पताल दत्तेवाड़ा में मरीजों की सुरक्षा और अस्पताल परिसर की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल में उपचार करने पहुंचे एक घायल मीडिया कर्मी ने आरोप लगाया कि इलाज के बाद जब वह अपनी स्कूटी लेने पहुंचा तो निर्धारित स्थान पर स्कूटी नहीं मिली। काफी देर तक तलाश करने के बाद स्कूटी अस्पताल परिसर में ही दूसरे स्थान पर मिली।

मीडिया कर्मी के अनुसार, सुबह स्कूटी से गिरने के कारण उसके पैर में चोट आई थी और उपचार के दौरान पैर में तीन टांके लगाए गए थे।

इसके बाद जब वह अस्पताल से वापस जाने के लिए अपनी स्कूटी लेने पहुंचा तो स्कूटी अपने स्थान पर नहीं मिली। घायल अवस्था में काफी देर तक वाहन की तलाश करनी पड़ी। 'सिविल सर्जन' के निर्देश पर रखवाई गई है"—कहने का आरोप- मीडिया कर्मी का आरोप है कि स्कूटी के संबंध में जब उसने अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों से जानकारी मांगी तो उसे बताया गया कि स्कूटी सिविल सर्जन के निर्देश पर किसी अन्य स्थान पर रखवाई गई है। इसके बाद उसे स्वयं ही वाहन तलाशने के लिए कहा गया।घायल अवस्था में वाहन की तलाश के लिए अस्पताल परिसर में भटकने की इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और मरीजों के प्रति संवेदनशीलता को

लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार को लेकर पहले भी उठते रहे सवाल- घटना के बाद अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले कर्मियों के व्यवहार को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। आरोप है कि मरीजों और उनके परिजनों तथा सुरक्षा कर्मियों के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बनती रहती है।ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि जब अस्पताल आने वाले मीडिया कर्मी के साथ ही कथित तौर पर इस तरह की स्थिति बन सकती है, तो दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से उपचार के लिए आने वाले सामान्य मरीजों और उनके परिजनों को सुरक्षा कर्मियों से किस तरह का व्यवहार झेलना पड़ता होगा।

सेवा संकल्प अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन 56 लोगों ने कियारक्तदान

दत्तेवाड़ा। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अजय रामटेके मार्गदर्शन में आज सेवा संकल्प अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया उक्त रक्तदान शिविर स्वास्थ्य विभाग एवं रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा दत्तेवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। जिसमें आदर्श महाविद्यालय जवांगा के यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी इकाई द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित की गई। रक्तदान शिविर में 56 से अधिक लोगों ने अपना रक्तदान किया। शिविर में ब्लड बैंक इकाई प्रभारी डॉक्टर रवि शंकर खटकड़ के द्वारा लोगों को रक्तदान का विशेष महत्व समझाते हुए भविष्य में भी रक्तदान करने के लिए



प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग से ब्लड बैंक महाविद्यालय के प्राचार्य ,प्राध्यापक

पोटा केबिन बेंगलूर में विकासखंड स्तरीय आयोजन, विद्यार्थियों ने चित्रकला, भाषण और पहाड़ा वाचन में दिखाया हुनर

टैलेंट शो में चमकी प्रतिभाओं की रोशनी, सेवा संकल्प ने दिया समाजसेवा का संदेश

दत्तेवाड़ा/कटेकल्याण। विकासखंड कटेकल्याण अंतर्गत पोटा केबिन बेंगलूर में विकासखंड स्तरीय टैलेंट शो एवं सेवा संकल्प अभियान का आयोजन उत्साह और गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति कौशल का शानदार प्रदर्शन कर उपस्थित अतिथियों एवं शिक्षकों की खूब सराहना बटोरी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दत्तेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविंद कुंजाम, जनपद अध्यक्ष हिडुमा कवासी, शिक्षा समिति अध्यक्ष भीमसेन मंडवी,



जनपद सदस्य पालो मरकाम, पुष्पांजलि नाग एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष कटेकल्याण लक्ष्मीनारायण टेकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। चित्रों में उकेरी कल्पना, भाषण में दिखा आत्मविश्वास कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता सहित विभिन्न

गतिविधियां आयोजित की गईं। बच्चों ने चित्रकला के माध्यम से अपनी कल्पनाशीलता और सृजनात्मक सोच को रंगों में उकेरा, वहीं भाषण प्रतियोगिता में विभिन्न विषयों पर बौद्धिक अपने विचार रखकर आत्मविश्वास का परिचय दिया। बिना रुके पहाड़ा पढ़कर बच्चों

ने दिखाई शैक्षणिक दक्षता-टैलेंट शो में विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष गतिविधि भी आयोजित की गई। इसमें कक्षा तीसरी से पांचवीं तक के विद्यार्थियों ने हिंदी में 2 से 20 तक तथा कक्षा छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी में 2 से 25 तक के पहाड़े बिना रुके एवं समझकर पड़े। इस गतिविधि ने विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता को मंच प्रदान किया। सेवा संकल्प से बच्चों में सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश- कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में सेवा भावना, सामाजिक जिम्मेदारी, सकारात्मक सोच और समाज के प्रति संवेदनशीलता

विकसित करने का संदेश दिया गया। सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य बच्चों में केवल शैक्षणिक दक्षता ही नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक सरोकारों से जोड़ना और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना रहा। अतिथियों एवं अधिकारियों ने विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे के भीतर कोई न कोई प्रतिभा छिपी होती है, जरूरत है उसे पहचानकर उचित मंच देने की। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ रचनात्मक, सांस्कृतिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया गया।

जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी एवं जिला पंचायत सीईओ श्री एम. भार्गव के मार्गदर्शन में हुआ स्वच्छता श्रमदान और शपथ कार्यक्रम

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जिला पंचायत परिसर में श्रमदान

दत्तेवाड़ा। जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम. भार्गव के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में स्वच्छता ही सेवा एवं सेवा संकल्प पखवाड़ा अंतर्गत आज 01 अक्टूबर को जिला पंचायत परिसर में 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ' थीम पर स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया तथा स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली। कार्यक्रम का शुरुआत अतिथियों



द्वारा जिला पंचायत परिसर में वृक्षारोपण के साथ की गई। इसके पश्चात जनप्रतिनिधियों, पंचगणों, अधिकारियों-कर्मचारियों एवं ग्रामीणजनों ने सामूहिक रूप से श्रमदान करते हुए सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। इसी कड़ी

में जिले की सभी ग्राम पंचायतों में भी ग्रामीणों की सहभागिता से स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की गईं। सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई, श्रमदान एवं जनजागरूकता के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि स्वस्थ, सुंदर एवं स्वच्छ समाज के निर्माण की सामूहिक जिम्मेदारी है। जनभागीदारी से

'सेवा फ़र्स्ट इनोवेशन चौलैंज'' को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



दत्तेवाड़ा । सेवा संकल्प अभियान के तहत दत्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दत्तेवाड़ा एवं शासकीय अरविंद महाविद्यालय किरंदुल में युवाओं में नवाचार एवं रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ''सेवा फ़र्स्ट इनोवेशन चौलैंज'' आधारित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, दत्तेवाड़ा के महाप्रबंधक रविशंकर नेताम एवं प्रबंधक दयाराम कुरें द्वारा महाविद्यालय के

विद्यार्थियों को सेवा फ़र्स्ट इनोवेशन चौलैंज के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को अपने आसपास की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को पहचानकर उनके समाधान के लिए नवाचार आधारित आईडिया विकसित करने तथा चौलैंज में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया गया।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि नवाचार केवल नई तकनीक विकसित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी मौजूदा समस्या के लिए

सरल, उपयोगी एवं प्रभावी समाधान प्रस्तुत करना भी नवाचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विद्यार्थियों से अपने दैनिक जीवन, समाज एवं स्थानीय स्तर की समस्याओं पर विचार कर उनके व्यावहारिक समाधान के रूप में नए आईडिया विकसित करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय से सहायक प्राध्यापक डॉ. शारदा दत्ते, महाविद्यालय के सेवा संकल्प अभियान प्रभारी सहायक प्राध्यापक सुखराज नुरेटी,

अन्य सहायक प्राध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा नवाचार आधारित आईडिया विकसित करने और सेवा फ़र्स्ट इनोवेशन चौलैंज में भाग लेने के प्रति रुचि दिखाई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में रचनात्मक सोच, नवाचार एवं समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ावा देना तथा उन्हें अपने नए विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रोत्साहित करना रहा।

माँ दत्तेश्वरी तालाब में वृहद स्वच्छता अभियान चलाकर दिया स्वच्छता का संदेश

सेवा संकल्प एवं स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र एवं सेवा सेतु शिविर आयोजित

दत्तेवाड़ा। नगर पालिका परिषद दत्तेवाड़ा द्वारा सेवा संकल्प अभियान एवं स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर में सफाई मित्र शिविर एवं सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से नगरवासियों को विभिन्न जनकल्याणकारी सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी एवं सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गईं। शिविर में राशन, नल-जल, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि सहित विभिन्न सेवाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जहां नागरिकों को आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम का शुरुआत प्रातः माँ दत्तेश्वरी तालाब परिसर में वृहद स्वच्छता अभियान के साथ हुई। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पायल गुप्ता, उपाध्यक्ष श्री कैलाश



मिश्रा, पार्षदगण, नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी एवं नगरवासी उपस्थित रहे। सभी ने सामूहिक रूप से स्वच्छता अभियान में सहभागिता करते हुए तालाब परिसर एवं आसपास के क्षेत्र की साफ-सफाई की तथा स्वच्छ एवं सुंदर दत्तेवाड़ा के संकल्प को मजबूत किया। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पायल गुप्ता ने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल अभियान तक सीमित न रहकर हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बननी चाहिए।



उन्होंने नागरिकों से अपने घर, आसपास के क्षेत्र एवं सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने तथा दत्तेवाड़ा को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुंदर बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री अरुण ध्रुव ने कहा कि -स्वच्छता एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए नागरिकों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। आप सभी के सहयोग से ही हम दत्तेवाड़ा को स्वच्छ एवं



व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित कर सकते हैं।- उन्होंने नागरिकों से स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने, कचरा निर्धारित स्थान पर डालने तथा नगर पालिका द्वारा संचालित स्वच्छता गतिविधियों में निरंतर सहयोग देने की अपील की। सेवा संकल्प अभियान एवं स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम ने जनसेवा और स्वच्छता को एक साथ जोड़ते हुए नागरिकों की सुविधा एवं सहभागिता को बढ़ावा देने का संदेश दिया।



संक्षिप्त समाचार

सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर आयोजित कर सफाई मित्रों के स्वास्थ्य की जांच, PPE किट एवं सुरक्षा सामग्री का वितरण तथा सम्मान



बिलासपुर। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल में स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत थीम पर 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2026 तक स्वच्छता ही सेवा (साहस)-2026 अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करना तथा स्वच्छता को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना है। इसी क्रम में 30 सितम्बर 2026 को सफाई मित्र सुरक्षा, सेवा एवं सम्मान थीम के अंतर्गत मंडल के बिलासपुर, शहडोल, मनेन्द्रगढ़, कोरबा, रायगढ़, ब्रजराजनगर सहित सभी प्रमुख स्टेशनों में सफाई मित्रों के स्वास्थ्य की व्यापक जांच एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया । सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर डू सभा सफाई मित्रों के लिए मंडल के विभिन्न स्वास्थ्य इकाई एवं स्टेशन परिसर में सिसल विंडो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर स्वास्थ्य की व्यापक जांच सुनिश्चित की गई। शिविर में सफाई मित्रों के समग्र स्वास्थ्य का मूल्यांकन करते हुए विभिन्न आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। साथ ही सफाई मित्रों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, खान-पान में सुधार करने तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानियां बरतने के लिए जागरूक किया गया। PPE Kit एवं सुरक्षा सामग्री का वितरण डू 'सफाई मित्र सुरक्षा, सेवा एवं सम्मान' थीम के अंतर्गत आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में सफाई मित्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें PPE किट एवं आवश्यक सुरक्षा सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें सेफ्टी ग्लव्स, मारक, सेफ्टी जूते, रिफ्लेक्टिव जैकेट सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण शामिल रहे। इन सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से सफाई मित्रों को कार्यस्थल पर संभावित जोखिमों से बचाव के साथ सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सफाई मित्रों एवं स्वच्छताग्राहियों का सम्मान डू सफाई मित्र सुरक्षा, सेवा एवं सम्मान' थीम पर सफाई मित्रों एवं स्वच्छताग्राहियों को सम्मानित किया गया। स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने, अपने दायित्वों का समर्पण एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान के लिए उनके कार्यों की सराहना भी की गई ।

सितम्बर में सेवानिवृत्त हो रहे मंडल रेल परिवार के 02 अधिकारी सहित 15 सदस्यों को दी गई भावभीनी विदाई



बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के विभिन्न विभागों में कार्यरत सहायक मंडल अभियंता एवं सहायक मंडल परिचालन प्रबंधक सहित 15 रेल परिवार के सदस्य माह सितम्बर 2026 में अपनी गौरवशाली रेल सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मंडल कार्मिक सभाकक्ष में आयोजित सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त हो रहे समस्त कर्मचारियों को सम्मान विदाई दी गई । इस अवसर पर मंडल कार्मिक अधिकारी श्री यू.एस.एस. राव एवं सहायक कार्मिक अधिकारी श्री भारकर गुप्ता द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी व कर्मचारियों को बंदोबस्त भुगतान से संबंधित समस्त दस्तावेज, सेवा प्रशस्ति प्रमाण-पत्र एवं सेवा मैडल आदि प्रदान किया गया 7 इस दौरान मुख्य कार्यालय अधीक्षक (आईटी) श्री सेवक रजक द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उम्मीद कार्ड (मेडिकल) व बंदोबस्त से संबंधित नियमों से अवगत कराया गया 7 इस अवसर पर सेवानिवृत्त कर्मियों के परिजन, कल्याण निरीक्षक तथा कार्मिक निपटारा शाखा के कर्मचारीगण उपस्थित थे । मंडल के सेवानिवृत्त हो रहे 15 रेल परिवार के सदस्यों में परिचालन विभाग से 03, इंजीनियरिंग विभाग से 05, विद्युत विभाग से 03, यांत्रिक विभाग से 01, सिग्नल व दूरसंचार से 02, तथा कार्मिक विभाग से 01 कर्मचारी शामिल हैं ।

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता ही समृद्धि थीम पर चलाया गया सघन जागरूकता अभियान.....

कबाड़ से जुगाड़और प्लास्टिक रिसाइक्लिंग पर दिया गया जोर

बिलासपुर। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल में स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत थीम पर 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2026 तक स्वच्छता ही सेवा (साहस)-2026 अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करना तथा स्वच्छता को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना है। इसी क्रम में 28 एवं 29 सितम्बर 2026 को स्वच्छता ही समृद्धि थीम के अंतर्गत बिलासपुर मंडल के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों, वर्कशॉप, कैंटीन एवं अन्य रेलवे परिसरों में कबाड़ से जुगाड़, कबाड़ से कला तथा प्लास्टिक वेस्ट के पुनर्चक्रण से संबंधित विशेष गतिविधियां आयोजित की गई। कबाड़ से जुगाड़-बेकार सामग्री को दिया उपयोगी रूप -इस अभियान के अंतर्गत रेलवे के अनुपयोगी एवं पुराने कबाड़, जैसे पुराने उपकरण, लोहे के टुकड़े, अनुपयोगी पुर्जे एवं अन्य धातु स्कूप का रचनात्मक उपयोग करते हुए उन्हें उपयोगी वस्तुओं एवं आकर्षक कलाकृतियों में परिवर्तित करने की पहल की गई । वर्कशॉप एवं स्टेशनों से निकलने वाले पुराने स्कूप से डस्टबिन, बेंच, फ्लावर पॉट, सेल्फे बोर्ड सहित अन्य उपयोगी एवं सजावटी वस्तुएं तैयार कर उन्हें रेलवे स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों एवं अन्य परिसरों में उपयोग/प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा । इससे अनुपयोगी सामग्री के पुनः उपयोग को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। कबाड़ से जुगाड़ की यह पहल यह सुनिश्चित

बिलासपुर में राजभाषा पखवाड़ा 2026 का पुरस्कार वितरण समारोह तथा क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बिलासपुर की 78वीं बैठक संपन्न.....

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर में रेलवे मुख्यालय तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बिलासपुर (कार्यालय) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए दिनांक 14 सितंबर 2026 से 28 सितंबर 2026 तक राजभाषा पखवाड़ा 2026 का आयोजन किया गया । इस पखवाड़े का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह तथा क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बिलासपुर की 78वीं बैठक श्री तरुण प्रकाश, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर की अध्यक्षता में आज दिनांक 28, सितंबर 2026 को महाप्रबंधक कार्यालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर में संपन्न हुआ । कार्यक्रम के आरंभ में मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, श्री बिजय कुमार ने महाप्रबंधक, सभी विभागाध्यक्षों तथा मंडलों/कारखानों से पधारे सभी सदस्यों का स्वागत किया । तत्पश्चात महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर

स्थित रवीन्द्रनाथ टैगोर, केंद्रीय पुस्तकालय को उन्नत बनाने तथा पाठकों को ऑनलाइन पठन-पाठन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 10 नग किंडल उपकरणों का विमोचन श्री तरुण प्रकाश, अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक के करकमलों से किया गया । राजभाषा पखवाड़ा-2026 के अंतर्गत रेलवे मुख्यालय बिलासपुर में राजभाषा नीति एवं सवैधानिक प्रावधानों पर हिंदी कार्यशाला, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती एवं राजभाषा संगोष्ठी, यूनिकोड एक्टिवेशन एवं टेबल ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रमों के साथ ही हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण आलेखन, हिंदी वाक, स्वरचित हिंदी काव्य पाठ एवं गीत गायन प्रतियोगिता तथा हिंदी पुस्तक समीक्षा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा प्रेरणा स्थान प्राप्त करने वाले रेलवे मुख्यालय, बिलासपुर के 20 तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बिलासपुर



(कार्यालय) के 16 पुरस्कार विजेता अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के करकमलों से पुरस्कृत किया गया । इस अवसर पर क्षेत्रीय रेल हिंदी नाट्योत्सव-2026 में क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले नागपुर मंडल के नाटक धड़ीचा, प्रधान कार्यालय के नाटक अविघ्नेया, रायपुर मंडल के नाटक तृष्णा तथा

बिलासपुर मंडल के नाटक वापसी के साथ ही क्षेत्रीय रेल हिंदी प्रश्नोत्तरी (क्रिज) प्रतियोगिता-2026 के कुल 03 विजेता कर्मचारियों को भी महाप्रबंधक, श्री तरुण प्रकाश द्वारा पुरस्कृत किया गया । इसके पश्चात श्री बिजय कुमार, मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, द.पू.म.रेलवे, बिलासपुर ने क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बिलासपुर की 78वीं बैठक की कार्यसूची पर चर्चा करते हुए जून 2026 को

समाप्त तिमाही में हुई राजभाषा प्रगति पर मदवार आंकड़े प्रस्तुत किये, जिस पर बैठक में उपस्थित सदस्यों ने विस्तारपूर्वक चर्चा की । अपने अध्यक्षीय उद्घोषण में अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक, श्री तरुण प्रकाश ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर को वर्ष 2025-26 के दौरान राजभाषा नीति के उल्लेखनीय कार्य-निष्पादन के लिए उत्कृष्ट श्रेणी में सम्मानित किये जाने पर रायपुर मंडल को बधाई दी । इस अवसर पर उन्होंने राजभाषा पखवाड़ा-2026 के दौरान रेलवे मुख्यालय तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बिलासपुर के सदस्य कार्यालयों के विजेता अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ही क्षेत्रीय रेल हिंदी नाट्योत्सव-2026 तथा क्षेत्रीय रेल हिंदी प्रश्नोत्तरी (क्रिज) प्रतियोगिता के विजेता कर्मचारियों को भी बधाई देते हुए कहा कि आप सभी के सामूहिक प्रयासों से रेल तथा बिलासपुर नगर के केंद्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार में वृद्धि हो रही है ।

लोको शेड बिलासपुर में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया

बिलासपुर। रेल प्रशासन द्वारा सविन्दा कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने , बीमारी से बचाव वाली स्वास्थ्य देखभाल की आदतों को मजबूत करने तथा स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल के लोको शेड में लोको हेल्थ यूनिट बिलासपुर द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया । आयोजित स्वास्थ्य शिविर के अत्यधिक पोषण, स्वस्थ जीवनशैली एवं परिवार की समग्र भलाई को प्रमुखता से केंद्रित किया गया। शिविर के दौरान सविन्दा कर्मचारियों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार, नियमित दिनचर्या तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही परिवार के बेहतर स्वास्थ्य



एवं खुशहाल वातावरण के लिए बच्चों की जिम्मेदार परवरिश, उनके स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास पर ध्यान देने तथा मोबाइल एवं डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित करने के संबंध में भी जागरूक किया गया। स्वास्थ्य शिविर के दौरान कुल 38 सविन्दा कर्मचारियों के स्वास्थ्य की व्यापक जांच सुनिश्चित की गई। शिविर में कर्मचारियों के समग्र स्वास्थ्य का मूल्यांकन करते हुए विभिन्न आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। इसके अंतर्गत

एंशोपोमेट्रिक माप, बांडी मास इंडेक्स (बन्धु), ब्लड प्रेशर तथा रैडम ब्लड शुगर की जांच की गई एवं सभी कर्मचारियों को टेनसन के टीके लगाए गए । एनीमिया की पहचान के लिए क्लिनिकल स्क्रीनिंग तथा सामान्य स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया गया। इन जांचों के माध्यम से कर्मचारियों के स्वास्थ्य की प्रारंभिक स्थिति का आकलन करते हुए उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, खान-पान में सुधार करने तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानियां बरतने के लिए जागरूक किया गया।

विश्व हृदय दिवस पर एसईसीएल मुख्यालय में हृदय स्वास्थ्य जागरूकता वेबिनार आयोजित

बिलासपुर। 29 सितंबर 2026 को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के चिकित्सा विभाग द्वारा आज मुख्यालय के सीएमडी कॉन्फ्रेंस हॉल में हृदय स्वास्थ्य जागरूकता वेबिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुबन्, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री हिमांशु जैन एवं निदेशक (तकनीकी)हंसचालन श्री रमेश चंद्र महापात्र उपस्थित रहे। मुख्यालय के विभागाध्यक्षों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विभिन्न क्षेत्रों से आए चिकित्सकों के साथ मुख्य चिकित्सा सेवाएं अधिकारी डॉ. श्रुतिदेव मिश्रा

भी उपस्थित रहे। 'हृदय रोगों की रोकथाम एवं शीघ्र पहचान' विषय पर अपोलो हॉस्पिटल्स, जुबली हिल्स, हैदराबाद के डॉ. पी. सी. रथ ने विशेषज्ञ व्याख्यान दिया। उन्होंने हृदय रोगों के प्रमुख जोखिम कारकों और शुरुआती लक्षणों की जानकारी देते हुए समय पर जांच एवं चिकित्सकीय परामर्श के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और तनाव प्रबंधन को हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। वेबिनार में एसईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों ने ऑनलाइन माध्यम से भी भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. ए. एस. जैन ने किया।

विशेष अभियान 6 के तहत एसईसीएल ने सफाई मित्रों के लिए लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर.....

बिलासपुर। विशेष अभियान 6 एवं स्वच्छता ही सेवा 2026 के तहत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा सोमवार को बिलासपुर स्थित इंदिरा विहार हेल्थ सेंटर में सफाई मित्रों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसईसीएल इन्दिरा विहार कॉलोनी में कार्यरत सविन्दा सफाई कर्मियों, जिमें महिला सफाई कर्मी भी शामिल रहें, का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर के दौरान सफाई कर्मियों के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट तथा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट सहित विभिन्न जांचों की गई। चिकित्सकों द्वारा सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिया गया।



जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यकतानुसार आगे चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाइयां प्रदान की जाएंगी। शिविर का उद्देश्य स्वच्छता व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सफाई मित्रों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। शिविर में पहुंचे लाभार्थियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि एक ही स्थान पर विभिन्न स्वास्थ्य जांच

एवं चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा मिलने से उन्हें अपने स्वास्थ्य की स्थिति जानने और आवश्यक सलाह प्राप्त करने में मदद मिली। स्वच्छता ही सेवा में सफाई मित्रों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर विशेष जोर- देशभर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है। अभियान के प्रमुख स्तंभों में

'सफाईमित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर' भी शामिल है, जिसके तहत सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरणों तथा पात्र कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने जैसी गतिविधियों पर जोर दिया गया है। एसईसीएल द्वारा यह स्वास्थ्य शिविर विशेष अभियान 6 के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता एवं जन-जागरूकता प्रयासों से भी जुड़ा है। विशेष अभियान 6 का मुख्य कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा, जिसमें स्वच्छता एवं लंबित मामलों के निपटारे के साथ इस वर्ष ई-वेस्ट के प्रभावी संग्रहण, पुथक्करण एवं निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 एवं विशेष अभियान 6 के तहत एसईसीएल द्वारा स्वच्छता गतिविधियों के साथ विभिन्न जागरूकता एवं सहभागिता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

सिम्स की व्यवस्थाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई, 31 एडवांस्ड मशीनों की खरीदी प्रक्रिया जारी

बिलासपुर। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) की व्यवस्थाओं और बुनियादी सुविधाओं को लेकर दायर जहनिट याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया है। वहीं उपकरण खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ मेंडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) ने नया शपथ पत्र पेश करने के लिए 10 दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। सुनवाई के दौरान मार्च और अप्रैल में किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट का भी

उल्लेख किया गया। कोर्ट कमिशनरों की रिपोर्ट में सिम्स में पानी के रिसाव की समस्या और अस्पताल के कई हिस्सों में पानी भरने की स्थिति का जिक्र किया गया। रिपोर्ट में फायर फाइटिंग सिस्टम लंबे समय से बंद होने की बात भी सामने आई। इस पर शासन की ओर से बताया गया कि फायर फाइटिंग सिस्टम की मरम्मत करा दी गई है। इससे पहले सीजीएमएससी ने भी हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर सिम्स के लिए खरीदी जा रही मशीनों और उपकरणों की स्थिति की जानकारी दी थी। शपथ पत्र के अनुसार सिम्स के लिए कुल 31 एडवांस्ड मशीनों की खरीदी प्रक्रिया चल रही है।



करता है कि हर अनुपयोगी वस्तु कचरा नहीं होती, बल्कि रचनात्मक सोच और उचित उपयोग के माध्यम से उसे उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है। प्लास्टिक वेस्ट का पुनर्चक्रण -स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्रमुख स्टेशनों, रेलवे कैंटीन,

वैंडिंग स्टॉल, रेलवे कॉलोनियों एवं अन्य परिसरों से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे के संग्रहण एवं उचित निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया गया । मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों के वैंडों एवं कैंटीन संचालकों को प्लास्टिक कचरे को अलग-अलग एकत्र करने तथा उसे अधिकृत रीसाइक्लर्स तक पहुंचाने के लिए जागरूक किया गया । साथ ही स्टेशनों एवं रेलवे कॉलोनियों से एकत्रित प्लास्टिक कचरे को अधिकृत रीसाइक्लर्स/स्थानीय निकायों के माध्यम से उचित पुनर्चक्रण के लिए भेजने की व्यवस्था को मजबूत किया गया । इस पहल का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को खुले में फेंके जाने अथवा अनुचित तरीके से निस्तारित किए जाने की प्रवृत्ति को रोकना तथा प्लास्टिक के कचरों एवं अपशिष्ट पदार्थों के बेहतर रिसाइक्लिंग की अवधारणा को बढ़ावा देना है।

मीन तशिः - मीन राशि वाले को गुरुवार 1 अक्टूबर 2026 को अपने काम पर पुरा ध्यान रखे, कार्यक्षेत्र में अच्छा काम करने का मौका मिलेगा और आगामी भूतनत की सहायता होगी, देवी और समग्रदशरूप से पवित्रता को महत्वपूर्ण काम पर काम पराएंगे, आगामी किसी पारिवारिक समस्या का समाधान होगा, किसी बुजुर्ग और अशुभनी व्यक्ति से आगामी सहयोग मिल सकता है। दिन के पहले भाग में वंदना दूसरे भाग में होकर आगामी किसी बात में उत्सुका सकते हैं। आगामी अतिरिक्त की स्थिति में रहेगे।

पेंशन-ग्रेच्युटी बहाली के लिए कल्याण कॉलेज के सामने त्यथित प्रोफेसर्स का प्रदर्शन, सपोर्ट में उतरे एक्स स्टूडेंट्स, सौपा ज्ञापन

इन कॉलेजों से पढ़कर निकले विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों का तगड़ा समर्थन, कहाँ लड़ेंगे आर-पार की लड़ाई

त्यथित और आक्रोशित प्रोफेसर्स ने कहा सड़क से संसद तक और डीएम से सीएम और पीएम तक जाएंगे

भिलाई। राज्य शासन द्वारा अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों की पेंशन तथा ग्रेच्युटी पर रोक लगाए जाने के फैसले के विरोध में भिलाई स्थित कल्याण कॉलेज के समक्ष सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में दुर्ग-भिलाई के अनुदान प्राप्त कॉलेजों के सेवानिवृत्त और सेवारत प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों ने एकजुट होकर शासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया और रोके गए भुगतानों को तुरंत बहाल करने की मांग की। इसमें कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुरना महाविद्यालय और भिलाई महिला महाविद्यालय के प्राध्यापक और कर्मि शामिल हुए।

वक्ताओं ने उच्च शिक्षा विभाग पर मंत्री परिषद के निर्णय की गलत और मनमानी व्याख्या करते हुए पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि राज्य शासन ने एक सितंबर

2026 से अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापक एवं कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान रोकने का निर्णय लागू किया है। धरने पर बैठे सेवानिवृत्त व सेवारत शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और प्रदेश के भावी नागरिकों तथा युवाओं का भवित्त्व संवारने में समर्पित कर दिया। लेकिन जीवन के इस ढलते पड़ाव में सरकार के इस बेतुके और अमर्यादित निर्णय ने उनके सम्मानजनक ढंग से जीने की उम्मीदों को तार-तार कर दिया है। सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय असुरक्षा के कारण उनके समक्ष जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है।

शिक्षा बिमरादरी से पछुंठी तमाम हरितियां - यह एक दिवसीय सांकेतिक धरना छत्तीसगढ़ राज्य अनुदान प्राप्त प्राध्यापक एवं कर्मचारी संघ, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों की पेंशन व ग्रेच्युटी बहाली संघर्ष समिति तथा सेवानिवृत्त एवं सेवारत प्राध्यापक व कर्मचारी संघ भिलाई-दुर्ग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। सेवानिवृत्त प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉ.हरिनारायण दुबे, प्रो.डी.पी.जायसवाल, प्रो.डी.एन.शर्मा, प्रो.रमेश



उपाध्याय, डॉ.आर.पी.अग्रवाल, डॉ.संध्या मदन मोहन, प्रो.जी.के.भावानी, सेवारत मंच से संघ के अध्यक्ष डॉ.सुधीर शर्मा, डॉ.अनुराग पांडेय एवं प्रो.लखन चौधरी, डॉ.सलीम अकौल, प्राचार्य

एलुमनी के छात्र और वित्तमंत्री से मार्मिक आग्रह - धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भिलाई के कल्याण कॉलेज के ही पूर्व छात्र और प्रदेश के वित्तमंत्री ओपी चौधरी को विशेष रूप से याद किया। सेवानिवृत्त प्राध्यापकों ने भावुक होकर कहा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी इसी महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर आज राज्य के उच्च पद पर आसीन हैं। ऐसे में अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में पेंशन और ग्रेच्युटी की बहाली का निर्णय शीघ्र लेना चाहिए।

एलुमनी के दिग्गज पहुंचे - प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी जायज मांगों पर शीघ्र सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पेंशन व ग्रेच्युटी बहाल नहीं किए तो यह सांकेतिक आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक रूप धारण करेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पूर्व विद्यार्थी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। महाविद्यालय के एलुमनी और पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट राजेश चौहान ने कहा कि गुरुजनों को दुखी करना और संकट में डालना दुःखद है। बी.विश्वनाथ ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को स्वयं

आकर संज्ञान लेना चाहिए। भिलाई में शिक्षा की नींव है कल्याण कॉलेज और नींव के पत्थर रखने वाले आज सड़क पर उतरने मजबूर हैं। अंजनी कुमार श्रीवास्तव, अल्ताफ अहमद, हरचरण सिंह, प्रभा हुसैन, योगेश गुप्ता, ज्ञानचंद जैन, आचार्य महेश शर्मा, लक्ष्मीपति राजू सहित अनेक पुराने विद्यार्थियों ने सभा को संबोधित किया। सभी ने एक स्वर में शासन से अपील की है कि पेंशन और ग्रेच्युटी बंद करने का आदेश निरस्त करें। कल्याण महाविद्यालय के धारा 28 के शिक्षक संघ की अध्यक्ष डॉ. आरती मिश्रा के साथ शिक्षकों ने आकर समर्थन व्यक्त किया।

पीएम-सीएम को सौपा ज्ञापन - बाद में प्रो.हरिनारायण दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिलाधीश दुर्ग को सौपा। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल, कल्याण कॉलेज एल्युमिनी संघ के अध्यक्ष योगेश गुप्ता, आलोक मिश्रा, विकास सिन्हा सहित आंदोलन में दो सी से अधिक शिक्षक और उतने ही पूर्व विद्यार्थी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में सीमा सुरक्षा बल का प्रेरक आयोजन, भिलाई में सफल रक्तदान शिविर सम्पन्न



भिलाई। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस (1 अक्टूबर) के उपलक्ष्य में सामरिक मुख्यालय महानिरीक्षक (विशेष-संक्रिया), सीमा सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़ के रिसाली स्थित मुख्यालय में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन श्री संजय पंत, महानिरीक्षक, सामरिक मुख्यालय (विशेष-संक्रिया), सीमा सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़ के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों, जवानों तथा शासकीय जिला चिकित्सालय, दुर्ग के मेडिकल स्टाफ ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। शिविर का आयोजन प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक हुआ, जिसके दौरान सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा



कुल 60 यूनिट रक्तदान किया गया। एकत्रित रक्त समाज के जरूरतमंद रोगियों के उपचार में उपयोगी साबित होगा। इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों एवं अधिकारियों ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी प्रतिभागियों को नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के समापन पर श्री

पेवर ब्लॉक घोटाला : शहर सरकार एफआईआर नहीं करवाती तो न्यायालय जाएंगे - रिकेश सेन

भिलाई नगर। भाजपा पार्थदों द्वारा शिकायत की जांच के आधार पर नगर निगम के वार्डों में घंटिया और माफदंड से कम पेवर ब्लॉक लगाकर सरकारी राशि के दुरुपयोग का मामला अब तूल पकड़ चुका है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने इस बड़े आर्थिक भ्रष्टाचार को पूरी मुखरता से उठाते हुए शहर की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। विधायक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों पर दो से तीन दिनों के भीतर प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई, तो मामले को न्यायालय लेकर जाने की तैयारी है।

जांच में खुली धांधली की पोल-कलेक्टर द्वारा गठित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की जांच कमेटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि निगम क्षेत्र के लगभग 21 वार्डों में तय तकनीकी मापदंडों की अनदेखी कर घंटिया और निश्चित दूरी से कम पेवर ब्लॉक बिछाए गए। इसके बावजूद नगर निगम के तकनीकी अमले ने ठेका एजेंसी को पूरा भुगतान पास कर दिया। रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया



8 सब इंजीनियर्स को दोषी ठहराते हुए 16 लाख रुपये से अधिक की रिकवरी निकालने की अनुशंसा की गई है।

विधायक का कड़ा रुख, बोले-सिर्फ सब इंजीनियर नहीं, बड़े अप्सरों पर भी हो कार्रवाई- विधायक रिकेश सेन ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह केवल छोटे

कर्मचारियों की लापरवाही नहीं है। भुगतान की पड़लें सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता और अधीक्षण अभियंता के हस्ताक्षरों से होकर गुजरी थी। ऐसे में सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए पूरी तकनीकी चेन जिम्मेदार है। उन्होंने मांग की है कि 8 सब इंजीनियर्स के साथ-साथ पड़लों को अप्रसारित करने वाले सभी वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उन पर आपराधिक मामला दर्ज हो।

एफआईआर दर्ज न होने पर कोर्ट की तैयारी- विधायक रिकेश सेन ने नगर निगम प्रशासन और शहर सरकार को दो टूक कहा है कि दोषियों को बचाने का प्रयास बदोशत नहीं किया जाएगा। यदि निगम प्रशासन तत्काल प्रभाव से दोषी ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाता है, तो न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। इस चेतावनी के बाद निगम के संबंधित गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है।

बच्चों के लिए खिलौना दान करने की अपील आंगन मिलन सेवा चौपाल में जुटे ग्रामीणजन



डोंगरगांव नगर। ब्लॉक के आंगनवाड़ी केन्द्र अर्जुनी क्र.1,2,3,4,5,6 में सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत आंगन मिलन सेवा चौपाल का आयोजन में किया गया। शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए पालकों से खिलौना दान करने की अपील की गई। इस

मितामिन का सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना की हितग्राही एवं महतारी वंदना की हितग्राही से मातृ संवाद किया गया। बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। हर घर मुनगा, घर घर मुनगा अभियान के बारे में बताया गया। मुनगा का पौधा लगाने हेतु प्रेरित करते हुए आंगनवाड़ी केन्द्र में मुनगा का पौधारोपण भी किया गया।कार्यक्रम में मुख्यअतिथि नेहा जैन, वरिष्ठनेता दिनेश साहू, विजय जैन, पूनम साहू, नागेश धनकर, द्रोपदी साहू, दौश सिन्हा, मैया लाल साहू, पंचगण, एएनएम आरती सोनी, मितामिन, गर्भवती माता, शिशुवती माता, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं ग्रामवासीजन उपस्थित थे।

विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन



बेमेतरा। सेवा संकल्प अभियान के तहत जनसेवा के प्रति विकसित भारत 2047 का सामूहिक संकल्प लेने तथा आगामी दशकों में विद्यार्थियों की संकल्पना और सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकासखंड स्तरीय भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन आज 28 सितम्बर को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा में किया गया जिसमें विकासखंड बेमेतरा के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दीपेश साहू विधायक बेमेतरा, विशिष्ट अतिथि अवधेश चंदेल पूर्व विधायक, राजेन्द्र शर्मा पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, विजय सिन्हा नगर पालिका अध्यक्ष, संध्या परगनिहा, निशा चौबे की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ बेमेतरा

विधायक दीपेश साहू द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथियों का स्वागत बीईओ कामिनी महिलांग तथा बीआरसी राजेन्द्र कुमार साहू द्वारा पुष्प गुच्छ से किया गया। कार्यक्रम में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक वर्ग का कार्यक्रम दो पाली में क्रमशः आयोजित किया गया। जिसमें स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, सेना का सौर्य, नया कश्मीर, नक्सल मुक्त भारत, अधोसंरचना विकास और विकसित छत्तीसगढ़ जैसे ज्वलंत मुद्दों और भविष्य के प्रति जागरूक करने योग्य विषयों पर स्कूली छात्रों ने मुखरता से अपनी भावनाओं को मंच पर शब्दों से और फलों पर रंगों से उकेरा। भाषण प्रतियोगिता में चित्रकला प्रतियोगिता में भाषण प्रतियोगिता में प्राथमिक वर्ग से 25 तथा पूर्व माध्यमिक वर्ग से 25 विद्यार्थी प्रतिभागी रहे, इसी तरह चित्रकला प्रतियोगिता में प्राथमिक वर्ग से 43 तथा पूर्व माध्यमिक वर्ग से 30 विद्यार्थी प्रतिभागी रहे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रतिभागी 3 अक्टूबर को जिला स्तर पर सहभागिता करेंगे। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में कविता बाजुई प्राचार्य बेमेतरा, बहोरिक साहू व्याख्याता कुसुमी, भारती भूतलहरे अधीक्षिका कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बेमेतरा, लेखन सिंह वर्मा व्याख्याता मोहनदास, उमा जटव, सरिता बंजारे, रेणुका अग्रवाल सहित विकासखंड बेमेतरा के सभी संकुल समन्वयक उपस्थित रहे।

ज्ञानांजलि भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन



बत्तलीराजहरा। ज्ञानांजलि भवन में दिवंगत लक्ष्मी पाठक माता के निमित्त श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान परमात्मा को भोग स्वीकार करारकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। 85 वर्षीय लक्ष्मी पाठक माता जी पिछले 25 वर्षों से बत्तलीराजहरा ईश्वरीय विश्व विद्यालय से जुड़ी हुई थीं। वे चिखलाकसा गीता पाठशाला में छत्तीसगढ़ रत्न समाजसेवी डॉ. शिरोमणि माधुर के सानिध्य में निर्यात रूप से परमात्म ज्ञान का अध्ययन करती थीं और सेवाओं में

समर्पित रूप से सहयोग देती थीं। शांतचित्त, सिले स्वभाव और सादगीपूर्ण जीवन उनकी विशेष पहचान थी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में डॉ. शिरोमणि माधुर, पूर्णमा, आभा, शारदा, अंजली, सुमित्रा, वासंती, गीता मरकाम, विनोद कौरिक, पवन साहू, जानकी साहू, शिवकुमारी कौरिक, पुष्पा गनीर, ममता गनीर, ईश्वर गनीर, संगीता मोरियानी, पी. शंकर राव, गोपेश सोनवानी, जलम सिंह मरकाम सहित बड़ी संख्या में भाई-बहनों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग में 'न्यायश्रुति' एवं 'ई-साक्ष्य' पर विशेष प्रशिक्षण-सह-प्रस्तुतीकरण

दुर्ग। आज के न्यायालय सिर्फ फाइलों और कागजों तक सीमित नहीं है। गवाही डिजिटल माध्यम से दर्ज हो सकती है, उपस्थिति ऑनलाइन सुनिश्चित हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य न्यायिक कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

इसी बदलती न्यायिक कार्यप्रणाली को समझने और उसे व्यवहार में प्रभावी ढंग से अपनाने की दिशा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में आज "न्यायश्रुति एवं ई-साक्ष्य" विषय पर विशेष प्रशिक्षण-सह-प्रस्तुतीकरण आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के. विनोद कुनूर के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें समस्त न्यायाधीशगण ने सहभागिता की।

Technology in Courtroom: अब सिर्फ भविष्य नहीं, वर्तमान है- नए अपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रिया-व्ययन के साथ न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हो रही है। इसी संदर्भ में

कार्यक्रम में न्यायश्रुति एप्लिकेशन तथा ई-साक्ष्य के व्यावहारिक उपयोग पर विशेष फोकस रखा गया। श्री प्रशांत पाराशर, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा श्री दीपक कुमार कोशले, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में श्री रवि कुमार मोहोबिया, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं था कि तकनीक क्या है, बल्कि यह समझाना था कि - इसे न्यायालयीन कार्यवाही में वास्तव में इस्तेमाल कैसे किया जाए?

न्यायश्रुति: जब साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया डिजिटल होती है- प्रस्तुतीकरण में न्यायश्रुति एप्लिकेशन के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करने तथा ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया। विभिन्न प्रक्रियाओं को व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिससे न्यायिक अधिकारियों को एप्लिकेशन की कार्यप्रणाली को अधिक सरल और प्रभावी ढंग से समझने में सहायता मिली।



यानी बाद सिफ एप्लिकेशन की नहीं थी - बात थी Courtroom Workflow को Technology के साथ जोड़ने की। **E-Sakshya:** डिजिटल साक्ष्य आया, अब उसकी न्यायिक यात्रा भी समझना जरूरी- कार्यक्रम में ई-साक्ष्य के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद उसके न्यायिक कार्यवाही में उपयोग से संबंधित प्रक्रिया पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। डिजिटल साक्ष्य से जुड़े तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं को उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया, ताकि न्यायिक अधिकारी उसके उपयोग की प्रक्रिया को व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझ सकें।

सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा—सवाल पूछे गए- प्रस्तुतीकरण को केवल one-way presentation नहीं रहा। न्यायिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न तकनीकी एवं व्यवहारिक प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित प्रक्रिया, संभावित व्यावहारिक परिस्थितियों और उनके समाधान से जुड़े पहलुओं

को स्पष्ट किया गया। यही संवाद इस प्रशिक्षण की विशेषता रहा - Technology को समझना और फिर उसे courtroom situations से जोड़कर देखना।

न्यायश्रुति और ई-साक्ष्य पर आयोजित यह विशेष प्रस्तुतीकरण न्यायिक प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के प्रभावी समावेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। इसका व्यापक उद्देश्य स्पष्ट है - तकनीक तभी न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाती है, जब उसे सही प्रक्रिया, सही समझ और सही तरीके से न्यायिक कार्यवाही में अपनाया जाए।-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग द्वारा न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निरंतर क्षमता-विकास और तकनीक-सक्षम न्यायिक कार्यप्रणाली के लिए आयोजित किए जा रहे ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम न्याय व्यवस्था को बदलती तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।